दाम वाली कारों की बिक्री 92% तक बढ़ी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

छोटी कारों का दौर लौट आया है। सरकार ने बीते साल सितंबर में छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी थी। इससे कीमतें 25-30% कम हो गईं। नतीजतन 5 लाख रुपए से कम की एंट्री-लेवल कारों की मांग में उछाल आया। 6 साल बाद छोटी कारों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 में हैचबैक कारों की बाजार हिस्सेदारी 24.4% हो गई, जो साल के पहले 9 महीनों में 23.5% थी। बीती तिमाही मारुति सुजुकी के मिनी सेगमेंट (अल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगनआर -सभी 5 लाख रुपए से कम) की बिक्री 92% बढ़ गई। बुकिंग इतनी ज्यादा है कि 1.5 महीने से डिलीवरी पेंडिंग चल रही है। इस बीच टाटा मोटर्स की टियागो की बिक्री 22% बढ़ गई। इसके सीएनजी वेरिएंट की बिक्री 34.5% और सीएनजी ऑटोमैटिक की बिक्री 41% बढ़ गई। कंपनी के मुताबिक, टैक्स घटने के बाद मासिक रिटेल बिक्री औसतन 50% बढ़ी है।

6 साल में पहली बार छोटी कारों का बाजार बढ़ा

दिसंबर में कार बिक्री 27% बढ़ी, 2025 की सबसे बड़ी मासिक उछाल, 84 लाख ज्यादा कारें बिकीं

- बिक्री बड़ी कारों से ज्यादा बढ़ने से 6 साल बाद छोटी कारों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी
- अक्टूबर-दिसंबर में हैचबैक की बाजार हिस्सेदारी 24.4% हो गई, जो 2025 के पहले 9 महीनों में 23.5% थी
- छोटी कारों की बिक्री में उछाल के चलते बीते दिसंबर में कारों की कुल बिक्री सालाना 27% बढ़कर 3.99 लाख हो गई, जो पिछले साल 3.15 लाख थी।
- वाहन कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक, यह 2025 के दौरान किसी एक महीने की बिक्री में सबसे बड़ा मासिक उछाल था।
- बीते दिसंबर में दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 84 लाख ज्यादा कारें बिकीं
- युवा खरीदारों और प्रीमियम एडिशन की वजह से ब्लैक कार का क्रेज बढ़ा है। 2025 में इनकी बाजार हिस्सेदारी 14.8% से बढ़कर 20.76% हो गई।
- 2025 में बिकीं करीब 30% एसयूवी काले रंग की थी, हैचबैक सेगमेंट में इस रंग की सिर्फ 6.77% कारें बिकीं • सबसे ज्यादा बिकने वाली सफेद कारों की बाजार हिस्सेदारी 43.9% से घटकर 40.7% रह गई।

बड़ी तैयारी...
ईवी उत्पादन बढ़ाने की स्कीम में बदलाव होगा!

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई एसपीएमईपीसीआई योजना में सरकार बदलाव कर सकती है। मार्च 2024 में शुरू हुई इस स्कीम में ग्लोबल ईवी कंपनियों 35,000 डॉलर से ज्यादा दाम वाली इलेक्ट्रिक कारें 15% शुल्क पर 5 साल इम्पोर्ट कर सकती हैं। बदले में भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करके फैक्ट्री लगानी होती है। लेकिन जनवरी, 2026 तक कोई आवेदन नहीं आया। इसलिए इसमें डायमेंट इंस्टिट्यूस जोड़े जा सकते हैं। वाहन कंपनियों ने सरकार को बताया है कि अगर मुक्त व्यापार समझौते के तहत इलेक्ट्रिक कारें आयात की जाएं तो बिना भारत में फैक्ट्री लगाए ही विस्तार किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार की स्कीम बेकार हो जाएगी।

ऑटो कारों के दिन लौटे, 5 लाख से कम कर रहा, ताकि ब्याज दरें कम ही रहें

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

कर्ज की लागत घटाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) बॉन्ड खरीद की रणनीति अपना रहा है। अप्रैल 2025 से अब तक आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी बॉन्ड खरीद चुका है। मकसद सिस्टम में नकदी बढ़ाकर ब्याज दरों को काबू करना है। हालांकि, संकेत अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। एक महीने में तीन महीने वाले सरकारी बॉन्ड की यील्ड 0.57% और 10 साल वाले बॉन्ड की 0.80% बढ़ी है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी निवेश में कमी को देखते हुए मार्च 2026 तक आरबीआई की 2 लाख करोड़ के और बॉन्ड खरीदने पड़ सकते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक सिस्टम में 7.7 लाख करोड़ रुपए की नकदी डाली जा चुकी है। इस दौरान रेपो रेट में भी 1.25% की कटौती की गई। इसके बावजूद बॉन्ड यील्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं घटी। इससे कर्ज की लागत कम नहीं हो पा रही।

प्रक्रिया: बॉन्ड खरीदकर नकदी बढ़ाई जाती है

ओएमओ नकदी नियंत्रित करने का प्रमुख टूल है। जब बाजार में पैसा कम होता है, तो आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदकर उन्हें नकदी देता है। बैंकों के पास फंड बढ़ने से वे कम ब्याज दर पर कर्ज देने की स्थिति में आते हैं। इससे आम आदमी के लिए होम, कार और बिजनेस लोन लेना सस्ता होता है।

असर: महंगा कर्ज निवेश और खपत के लिए बाधा

बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो गया है। इस वजह से होम लोन, ऑटो लोन और कॉरपोरेट लोन की दरें ऊंची बनी हुई हैं। यह निवेश और खपत दोनों को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए अब आरबीआई को बॉन्ड खरीद का दायरा बढ़ाना ही होगा।

संकट: राज्यों की भारी उधारी से नकदी पर दबाव

केंद्र ने उधारी योजना में 10,000 करोड़ की कटौती की है, लेकिन राज्य सरकारें मार्च तक 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। बॉन्ड की निरंतर सप्लाई बाजार की नकदी सोख लेती है। जब सरकार बहुत ज्यादा लोन लेती है, तो बाजार में पैसा कम होने से आम आदमी के लिए भी लोन महंगा हो जाता है।

गणित: बॉन्ड यील्ड बढ़ने से घटता है मुनाफा

बाजार में बॉन्ड की कीमतें गिरने पर यील्ड यानी रिटर्न बढ़ जाता है, जिससे पुराने निवेशकों का मुनाफा घट जाता है। वर्ष 2025 में भारतीय सरकारी बॉन्ड ने महज 6.7% रिटर्न दिया, जो तीन साल में सबसे कम है। इसके अलावा विदेशी बाजार में सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने देश में महंगाई के वास्तविक आंकड़ों को प्रभावित किया है। इसलिए विदेशी निवेश घटने से आरबीआई पर नकदी बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है।

बीएसई ने 4 नए मिडकैप फैक्टर इंडेक्स लॉन्च किए

मुंबई | बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बीएसई 150 मिडकैप इंडेक्स पर आधारित चार नए फैक्टर इंडेक्स शुरू किए हैं। इनमें एन्हांस्ड वैल्यू 30, मोमेंटम 30, लो वोलेटिलिटी 30 और क्वालिटी 30 इंडेक्स शामिल हैं। हर इंडेक्स मिडकैप कंपनियों में से 30 शेयरों को अलग-अलग मानकों पर ट्रैक करेगा। इन इंडेक्स में हर तीन महीने में बदलाव होगा। इनका इस्तेमाल ईटीएफ, इंडेक्स फंड और निवेश के अन्य पैसिव विकल्पों के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाएगा।

भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 144 गुना भरा

मुंबई | भारत कोकिंग कोल का 1,071 करोड़ रु. का आईपीओ आखिरी दिन 143.85 गुना सब्सक्राइब हुआ। 34.69 करोड़ शेयरों के लिए 4,990 करोड़ से भी अधिक शेयरों की बोलियां मिलीं। क्वालिफाइड संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 310.81 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 240.49 गुना और रिटेल निवेशकों ने 49.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। 21-23 रुपए प्रति शेयर कीमत और 10,700 करोड़ रु. की वैल्यूएशन पर ये इस साल का पहला मेनबोर्ड आईपीओ था।

नवाचार • 39% इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एआई के जिम्मे

एआई 40% तक तकनीकी काम कर रहा, पर इंसानी निगरानी जरूरी

भास्कर न्यूज़ | बेंगलुरु

देश के तकनीकी संगठनों में अब 20-40% काम एआई संभाल रहा है। आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई का दखल इससे भी ज्यादा है। आईटी कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था नैसकॉम और जॉब प्लेटफॉर्म इंडीड के एक सर्वे में शामिल 45% कंपनियों ने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 40% से ज्यादा हिस्सा एआई संभाल रहा है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का 39% और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का 37% काम या तो पूरी तरह एआई कर रहा है या बड़ी भूमिका निभा रहा है।

'फ्यूचर वर्क 2025' नाम के सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि एआई अब सिर्फ सहायक टूल नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा के निर्यमित काम में गहराई से जुड़ गया है। 97% एचआर (मानव संसाधन) लीडर्स का मानना है कि 2027 तक काम की प्रकृति इंसान और एआई के सहयोग से तय होगी। 95% से ज्यादा संगठन एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।

एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, पर नए हुनर की दरकार

सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा कंपनियों ने कहा कि एआई के आउटपुट अधूरे या कम क्वालिटी वाले होते हैं, इसलिए मानव निगरानी बहुत जरूरी बनी हुई है। एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि भूमिकाएं तेजी से बदल रही हैं। एंट्री-लेवल जॉब्स में अब लाइव प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और पोर्टफोलियो को डिग्री से ज्यादा महत्व मिल रहा है।

77% नियोक्ताओं को सुरक्षा की चिंता

- 77% एम्प्लॉयर्स को सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क की चिंता, 40% एचआर लीडर्स कर्मियों में एआई-रेडीनेस की समस्या से परेशान हैं।

करियर का असली मौका लोगों को एआई के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करने में है।
– केतकी कर्णिक, रिसर्च हेड, नैसकॉम

स्वतंत्रता पर एकजुटता

दुनिया के 11 केंद्रीय बैंक फेड प्रमुख पॉवेल के साथ

एजेंसी | वाशिंगटन

दुनियाभर के 11 प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। यह समर्थन तब आया, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की। बैंक ऑफ इंग्लैंड के एंड्रयू बेली, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा के टिफ मैकलम सहित 11 बैंकरों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें पॉवेल की ईमानदारी, जनहित में काम और ब्याज दर तय करने में उनकी स्वतंत्र सोच की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि पॉवेल एक सम्मानित सहकर्मी हैं और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक साल से पॉवेल पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ब्याज दरों को लेकर उनकी नीतियों की आलोचना की और उन्हें 'मेजर लूजर' यानी हारा हुआ व्यक्ति कहा। बहरहाल, ट्रम्प ने जांच के बारे में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह वैश्विक समर्थन केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के खिलाफ मजबूत संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पॉवेल की स्थिति को मजबूत कर सकता है। ट्रम्प हर हाल में ब्याज दरें घटाने चाहते हैं, लेकिन इस मामले में पॉवेल का रुख अलग है। उनका मानना है कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि ब्याज दरों और कम की जाएं।

29% की भारी गिरावट

भारत का रूसी क्रूड आयात दिसंबर में घटा

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश की सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी कमी की है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 में रूसी जीवाश्म ईंधन के खरीदारों में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया। 2.6 अरब यूरो (करीब 28 हजार करोड़ रु.) के रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद के साथ तुर्किये भारत को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया। 6 अरब यूरो (63 हजार करोड़ रु.) की खरीद के साथ चीन रूसी तेल का शीर्ष खरीदार बना हुआ है। सीआरईए के मुताबिक भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात में महीने-दर-महीने 29% की भारी गिरावट आई। यह गिरावट मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी के कारण हुई, जिसने दिसंबर में रूसी तेल से अपने आयात को आधा कर दिया। यह गिरावट तब आई है जब भारत का कुल तेल आयात थोड़ा बढ़ा है। यानी भारत अब रूस के बजाय दूसरे देशों से तेल खरीद रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹4 लाख करोड़ पार: वैष्णव

नई दिल्ली | देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025 में 4 लाख करोड़ रु. को पार कर गया। इसमें स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केवल आईफोन का निर्यात 2024 के मुकाबले दोगुना बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रु. तक पहुंच गया। इस साल देश में स्मार्टफोन उत्पादन करीब 30 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है। इसमें से एक चौथाई स्मार्टफोन निर्यात होंगे।

फ्रंट पेज के शेष

रिश्तों का कत्ल: 15 लाख के कर्ज से बचने के लिए पोते ने कर दी दादा-दादी की हत्या...

11 जनवरी की रात करीब 11:45 बजे रविंद्र अपने घर की दीवार फांदकर दादा के घर में घुसा और दरवाजा खोलकर अपने दोनों साथियों को अंदर बुलाया। तीनों ने मिलकर बुजुर्ग दंपती के हाथ-पांव बांधे और शोर न मचे, इसके लिए उनके मुंह पर पहले से खरीदी गई टेप चिपका दी। इसके बाद दोनों को गला घोंटकर हत्या कर दी गई। रविंद्र मंदिरों में पूजा-पाठ करता था, गौशाला में सेवा करता और खुद को 'बाबा' कहलवाता था। इसी धार्मिक चोले के पीछे एक नशेड़ी और अपराधी छिपा था, जिसने लालच में आकर वारदात की।

साजिश में दो और लोगों को लालच देकर शामिल किया : रविंद्र ने जयसिंहपुरा निवासी प्रदीप और गुलशन को लालच दिया कि दादा के कबाड़े के गोदाम में भारी मात्रा में तांबा रखा है। मकसद हत्या को लूट के दौरान हुई वारदात दिखाना था, ताकि शक बाहरी बदमाशों पर जाए।

56% टॉप लीडर्स बर्नआउट के शिकार; नेटफ्लिक्स, ओरेकल जैसी कंपनियां 'टो वॉस, एक विज़न' का फॉर्मूला अपना रहीं...

सीईओ टैलेंट और वर्क-लाइफ बैलेंस की जरूरत के चलते यह मॉडल तेजी से चर्चित हो रहा है। हालांकि यह हर कंपनी के लिए सफल नहीं रहा। सेल्सफोर्स, एसएपी और मार्क्स एंड स्पेंसर में सह-सीईओ व्यवस्था दो साल से भी कम समय चली। बिजनेस कंसल्टेंसी कॉन रेची की टियर्नी रेमिक के अनुसार, यह मॉडल उन्हीं कंपनियों में बेहतर काम करता है जहां दोनों लीडर्स पहले से साथ काम कर चुके हों। सही जोड़ी और स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ यह मॉडल कंपनियों को अधिक स्थिर नेतृत्व दे सकता है। अन्यथा शक्ति संघर्ष व संगठन में भ्रम की स्थिति बन सकती है।

सेना में महिला और पुरुषों को समान हक मिलेः सेना प्रमुख...

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार थी... 15 जनवरी को आने वाले सेना दिवस से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने कहा कि पिछले साल मई में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना जमीनी आक्रमण के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसने को पूरी तरह तैयार थी। हमारे टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले की तैयारी कर चुके थे। हम बस ये इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर कोई भी गलती करता है तो हम तुरंत जमीनी कार्रवाई शुरू कर देंगे।

ट्रम्प बेकाबू... अब ईरान से व्यापार करने वालों पर लगाया 25% टैरिफ...

जिसके अनुसार रूस से व्यापार करने पर 500% टैरिफ का प्रावधान है।

ईरान ने पहली बार माना... हिंसा में अब तक 2 हजार मौतें हो चुकीं तेहरान। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ बीते दो हफ्ते से जारी देशव्यापी विद्रोह में अब तक 2 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। यह जानकारी ईरान प्रशासन के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि मृतकों में कितने आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी हैं। उन्होंने कहा कि इन मौतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने विद्रोह भड़काया है। 10 हजार से ज्यादा लोग हिरासत में हैं।

'डिजिटल अरेस्ट' पर आखिरी प्रहार के लिए बनाई जा रही अचूक रणनीति...

कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, दूर संचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर शामिल है। गूगल, वॉट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टैक कंपनियां भी मदद कर रही हैं। कंपनियों के साथ इसे लेकर 6 जनवरी को एक बैठक हो चुक